



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 244]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 7, 2008/आषाढ़ 16, 1930

No. 244]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 7, 2008/ASADHA 16, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2008

जांच शुरुआत (निर्णायक समीक्षा)

**विषय :** चीन जनवादी गणराज्य के मूल के/वहाँ से निर्यातित टाइटेनियम डाइऑक्साइड के आयातों के मामले में निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जाँच की शुरुआत ।

सं. 15/5/2008—डीजीएडी.—यतः वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क या अतिरिक्त शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 (जिन्हें एतदपश्चात् नियम कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) ने दिनांक 6 जून, 2003 की अधिसूचना सं. 14/51/2002—डी जी ए डी के जरिए चीन जन.गण. (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित टाइटेनियम डाइऑक्साइड (एनाटेज टाइप) [जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है] के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी, जिसे 11 जुलाई, 2003 की अधिसूचना सं. 107/2003 के जरिए संबद्ध वस्तु पर लगाया गया था । प्राधिकारी ने दिनांक 15 मार्च, 2004 को अपने अंतिम जाँच परिणाम प्रस्तुत किए और दिनांक 9 अप्रैल, 2004 की अधिसूचना सं. 54/2004 के जरिए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था ।

## 2. समीक्षा हेतु अनुरोध एवं जाँच की शुरुआत

यतः सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 के अनुसार यदि पहले ही समाप्त न कर दिया गया हो तो पाटनरोधी शुल्क अपने अधिरोपण की तारीख से पाँच वर्षों की समाप्ति पर स्वतः ही समाप्त हो जाता है ।

बशर्ते यदि किसी समीक्षा में केन्द्र सरकार का विचार यह हो कि ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने या पुनः प्रारंभ होने की संभावना है, तो वह समय-समय पर ऐसे अधिरोपण की अवधि को और पाँच वर्षों के लिए बढ़ा सकती है और ऐसी अवधि ऐसे विस्तार के आदेश की तारीख से शुरू होगी ।

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार मै. त्रावनकोर टाइटेनियम प्रॉडक्ट्स लि. ने मै. किलबर्न कैमिकल्स लि. के समर्थन से एक विधिवत् प्रमाणित याचिका के साथ प्राधिकारी से ऐसी समीक्षा का अनुरोध किया । वर्ष 2006 की रिट याचिका सं. 16893 (इंडियन मेटल एंड फ़ैरो एलॉयज लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी) में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय जिसमें कहा गया है कि निर्णायक समीक्षा अनिवार्य है और ऐसी समीक्षा नियमावली के नियम 23 के अनुसार की जानी अपेक्षित है, के मद्देनजर निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात की जाँच करने के लिए कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहेगी अथवा उसकी पुनरावृत्ति होगी, अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार एतद्वारा निर्णायक समीक्षा की शुरुआत करते हैं ।

### 3. विचाराधीन उत्पाद

वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद चीन जन गण के मूल का अथवा वहाँ से निर्यातित टाइटेनियम डाइऑक्साइड एनाटेज ग्रेड है जिसका रासायनिक सूत्र  $TiO_2$  है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड एनाटेज एक श्वेत रंजक है और यह अत्यधिक श्वेत होता है। इसकी रंजक क्षमता तथा हाइड्रिंग शक्ति किसी भी अन्य रंजक से बेहतर है तथा प्रकाश और उष्मा में यह स्थिर व टिकाऊ भी बना रहता है। इसका प्रयोग मुख्यतः पेंट, प्लास्टिक, कागज, स्याही, रबड़ आदि के विनिर्माण में होता है और यह विषैला नहीं होता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड भारतीय व्यापार वर्गीकरण के अंतर्गत सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष 28.23.00 तथा 28.23.00.10 के तहत वर्गीकृत है तथापि यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जाँच के दायरे पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है। चूँकि यह ऐसे उत्पाद की निर्णायक समीक्षा है जिस पर पहले से ही शुल्क लागू है अतः विचाराधीन उत्पाद अपरिवर्तित रहेगा।

### 4. प्रक्रिया

जाँच यह निर्धारित करेगी कि क्या आय की समाप्ति से पाटन तथा क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है। प्राधिकारी यह जाँच करेंगे कि क्या पाटन को समाप्त करने के लिए शुल्कों को जारी रखना आवश्यक है और शुल्क समाप्त करने या परिवर्तित करने अथवा दोनों उपाय करने की स्थिति में क्या क्षति के जारी रहने अथवा दोबारा होने की संभावना है।

- i. इस समीक्षा में दिनांक 16 जनवरी, 2003 की अधिसूचना सं० 14/51/2002-डी जी ए डी के सभी पहलू शामिल होंगे।
- ii. जाँच में शामिल देश चीन जन गण है।
- iii. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जाँच अवधि 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2008 (12 माह) है।
- iv. इस समीक्षा पर उपरोक्त नियमावली के नियम 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 तथा 20 के प्रावधान यथाआवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

### 5. सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों, भारत/प्रतिनिधि देशों में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबंधित समझे जाने वाले आयातकों एवं प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए और निम्नलिखित को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है।

निर्दिष्ट प्राधिकारी

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी निर्धारित स्वरूप एवं ढंग से नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर जांच से संगत अपने निवेदन प्रस्तुत कर सकती है।

#### 6. समय-सीमा

वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना तथा सुनवाई के लिए कोई अनुरोध लिखित में दिया जाए जो प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर पहुँच जाने चाहिए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त नियमों के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं।

#### 7. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

नियमावली के नियम 6(7) के संदर्भ में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई किसी गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है गोपनीय सूचना के अगोपनीय रूपांतर अथवा अगोपनीय सारांश में पर्याप्त विवरण होना चाहिए ताकि अन्य हितबद्ध पार्टियों को उसका अर्थ स्पष्ट हो सके। यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार की राय में सूचना को सारांश में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है तो इसके कारण दर्शाते हुए एक विवरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होता है।

#### 8. उपलब्ध तथ्यों का उपयोग

यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है अथवा उचित अवधि के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है अथवा जाँच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

#### 9. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश रखे हुए हैं।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2008

Initiation (Sunset Review)

**Subject : Initiation of Sunset Review Anti-Dumping Investigations into imports of Titanium Dioxide originating in/exported from People's Republic of China.**

**No. 15/5/2008-DGAD.**—Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules,

1995 (herein after referred to as AD Rules), the Designated Authority (herein after referred to as the Authority) recommended provisional anti-dumping duty on import of Titanium Dioxide (Anatase Type) [hereinafter referred to as subject goods] originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as subject country), vide Notification No. 14/51/2002-DGAD dated 6<sup>th</sup> June 2003, which were imposed on the subject goods vide Notification No. 107/2003 Customs dated 11<sup>th</sup> July, 2003. The Authority came out with the final findings on 15<sup>th</sup> March, 2004 and definitive anti-dumping duty was imposed vide Notification No. 54/2004 dated 9<sup>th</sup> April 2004.

## **2. Request for Review and Initiation**

WHEREAS in terms of the Customs Tariff (Amendment) Act 1995, the anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition.

Provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension.

In terms of the above provisions, M/s Travancore Titanium Products Ltd., supported by M/s Kilburn Chemicals Ltd approached the Authority with a duly substantiated petition requesting for such a review. In view of the judgment of the Hon'ble Delhi High Court in the Writ Petition No 16893 of 2006 (Indian Metal & Ferro Alloys Ltd Vs Designated Authority) holding that sunset review is mandatory and such review is required to be carried out in terms of Rule 23 of the Rules, the Designated Authority hereby initiates the sunset review proceedings, in accordance with Section 9 A (5) of the Act, to examine whether cessation of the duty in force would lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

## **3. Product under consideration**

The product under consideration in the present petition is Titanium Dioxide Anatase grade, having chemical formula  $\text{TiO}_2$  originating in or exported from People's Republic of China. Titanium Dioxide Anatase is a white pigment and has a very high degree of whiteness. Its tinting strength and hiding power are superior to any other pigment, and it also has stability and durability against light and heat. It is primarily used in the manufacture of paints, plastics, paper, ink, rubber etc., and is not toxic. Titanium Dioxide is classified under Custom Tariff heading 28.23.00 and 28.23.00.10 under Indian Trade Classification. The classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation. This being a sunset review of the product against which duty is already in force the product under consideration shall remain unchanged.

#### 4. Procedure

The investigation will determine whether the expiry of the measure would be likely to lead to a continuation or recurrence of dumping and injury. The Authority will examine whether the continued imposition of the duties is necessary to offset dumping and whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both.

- i. The review will cover all aspects of Notification No 14/51/2002-DGAD dated 16<sup>th</sup> January, 2003.
- ii. The country involved is China PR.
- iii. The period of investigation for the purpose of the present review is from 1<sup>st</sup> April, 2007 to 31<sup>st</sup> March, 2008 (12 months).
- iv. The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rule supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

#### 5. Submission of information

The exporters in the subject country, their government through their Embassy in India/representatives, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the:

The Designated Authority  
(Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties)  
Government of India  
Ministry of Commerce & Industry  
Udyog Bhavan, New Delhi-110011.

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

#### 6. Time limit

Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than forty (40) days from the date of publication of this review notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

2555 GI/08-2

**7. Submission of information on non-confidential basis**

In terms of Rule 6(7), of the Rules the interested parties are required to submit non-confidential version of any confidential information provided to the Authority. The non-confidential version or non-confidential summary of the confidential information should be in sufficient detail to provide a meaningful understanding of the information to the other interested parties. If in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summary, a statement of reason thereof is required to be provided.

**8. Use of facts available**

In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

**9. Inspection of public file**

In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

R. GOPALAN, Designated Authority